Economic Times Hindi Edition Delhi
28.11.2016 Page 4
Height 15.37cm Width 7.67 cm

# गांवों में आधार से जुड़ा पेमेंट सिस्टम बनाने की तैयारी

[ धीरज तिवारी । नई दिल्ली ]

**ग्रामीण इलाकों** में कैश संकट और बैंक खातों की दिक्कत दूर करने के लिए सरकार आधार से जुड़ा पेमेंट सिस्टम तैयार करने में जुटी है। माइक्रो-एटीएम के जरिये इस सुविधा को अंजाम दिया जाएगा।

मामले से वाकिफ एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स फिलहाल बैंक के हिसाब से अलग-अलग सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स के जरिये ऑपरेट करते हैं। इससे अक्सर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाता है।

अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं किए जाने की शर्त पर बताया, 'हम तमाम संबंधित पक्षों से बात कर रहे हैं। इस पर काम चल रहा है।' आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) बैंक की अगुवाई वाला मॉडल है, जिसमें अलग-अलग बैंकों के हिसाब से बदलाव होता है। इसमें आधार के जरिये एक से दूसरे बैंकों में ट्रांजैक्शन को अंजाम दिया जाता है। हालांकि, एक से दूसरे बैंकों से ऑपरेशन में दिक्कत होने के कारण ट्रांजैक्शंस में दिक्कत हो रही है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के चेयरमैन ए पी होता ने भी इस घटनाक्रम की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इस मामले में यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) से उनकी बात चल रही है। उन्होंने कहा, 'इसका मकसद देशभर में माइक्रो एटीएम का तेजी से विस्तार हो रहा है। हम इसे तुरंत डिवेलप करने के लिए अलग-अलग विकल्पों की तलाश कर रहे हैं।' देश में कुल 1.26 लाख बैंक मित्र या बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो इन माइक्रो एटीएम या हाथ में रखे जाने वाले प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनल से ऑपरेट करते हैं। सरकार का इरादा मार्च 2017 तक देशभर की एक लाख से भी ज्यादा राशन दुकानों पर माइक्रो एटीएम मुहैया कराना है। साथ ही, बैंकों को इन राशन दुकानों को बिजनेस कॉरस्पॉन्डट की तरह अपग्रेड करने की सलाह दी गई है। देशभर में तकरीबन 5.5 लाख राश की दुकानें हैं।